Regarding movement of rice from godowns in Punjab

श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंग (लुधियाना) : माननीय सभापति महोदया, मैं आपका ध्यान एग्रीकल्चर बेस्ड राइस इंडस्ट्री की तरफ दिलाना चाहता हूँ ।

पिछले दो-तीन वर्षों से यह हो रहा है कि जब किसान का धान अक्टूबर-नवम्बर के महीने में आता है, तो सरकार धान खरीदने के बाद, राइस शेलर्स के साथ एग्रीमेंट करके, उनको धान शेलिंग के लिए देती है कि इसे शेलिंग करने के बाद केन्द्र सरकार की एफसीआई को देना है । पिछले तीन वर्षों से यह हो रहा है कि जानबूझकर किसान और एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री को बंद करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि अगर वह इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, तो किसान का धान नहीं उठाना पड़ेगा, इसलिए उनको परेशान किया जा रहा है ।

जो राइस शेलर्स हैं, जो शेलिंग करते हैं, वे मार्च में शेलिंग करके फ्री हो जाते हैं । सरकार को चावल वापस दे देते हैं । लेकिन अब यह हो रहा है कि केन्द्र सरकार की तरफ से राइस की मूवमेंट नहीं हो रही है । पहले राइस गोदामों से शिफ्ट होता था और जगह बनती थी और राइस शेलर्स शेलिंग करके वहाँ नया माल लगाते थे । अब वे छः-सात महीने तक पड़े हैं यानी नवम्बर-दिसम्बर में आएगा । अभी गर्मी का मौसम है । गर्मी के मौसम में वह ज्यादा ब्रोकेन हो जाता है, धान सूख जाते हैं । इसकी वजह से, यह इंडस्ट्री बंद हो रही है । पिछले साल, कम से कम चार-पाँच सौ राइस शेलिंग मिल्स बंद हो गए हैं ।

मेरी मांग है कि राइस मूवमेंट यानी गोदामों को खाली करने का काम केन्द्र सरकार करे ताकि किसान की फसल भी उठा ली जाए और राइस शेलर्स इंडस्ट्री, जो हमारे यहाँ एक ही बड़ी इंडस्ट्री है, वह भी किसी कारण से बंद न होने पाए ।